भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2226
सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

रोजगार कार्यालय

2226. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमारः
एडवोकेट डीन कुरियाकोस
थोमस चाज़िकाडनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण देश में रोजगार कार्यालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और उनमें कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं;
(ख) संपूर्ण देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किए गए व्यक्तियों की जिले-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या अनेक वर्षों में नौकरी चाहने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और क्या ऐसे कार्यालयों के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है;
(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों की निजीकरण की दर में जिले-वार कमी आई है या वृद्धि हुई है; और
(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से घ): राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों और रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं है कि सभी बेरोजगार हों, तथा देश में इन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजित रोजगार चाहने वालों की संख्या उपलब्ध सीमा तक अनुबंध-I में दी गई है। जिला-वार आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

(ङ एवं च) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में कोई भी निजी रोजगार कार्यालय कार्यरत नहीं है।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 02.12.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2226 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में उपलब्ध सीमा तक इन रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वालों तथा इनके माध्यम से किए गए नियोजन के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार का ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	रोजगार कार्यालयों की संख्या	रोजगार चाहने वाले (लाख में)			नियोजन (हजार में)		
			2015	2016	2017 (अगस्त तक अनंतिम)	2015	2016	2017 (अगस्त तक अनंतिम)
1	आंध्र प्रदेश	17	9.01	9.14	9.18	0.20	0.50	0.16
2	अरुणाचल प्रदेश	12	0.75	1.00	1.02	0.00	0.00	0.00
3	असम	52	18.13	19.27	19.47	0.85	0.60	0.55
4	बिहार	47	6.76	7.81	7.89	1.10	1.90	0.00
5	छत्तीसगढ़	26	17.95	21.57	22.51	3.18	0.20	0.25
6	दिल्ली	14	12.63	12.63	12.63	0.19	0.00	0.00
7	गोवा	1	1.33	1.19	1.19	2.91	1.10	0.00
8	गुजरात	48	6.77	5.98	5.85	336.67	330.10	274.43
9	हरियाणा	59	7.38	7.65	7.77	0.28	0.40	0.05
10	हिमाचल प्रदेश	15	8.20	8.31	8.35	1.11	1.50	0.25
11	जम्मू और कश्मीर	17	2.79	2.52	2.33	0.08	0.20	0.97
12	झारखंड	42	5.70	4.97	4.66	2.95	2.50	2.78
13	कर्नाटक	40	3.53	3.42	3.38	0.79	0.70	0.27
14	केरल	89	36.16	35.60	34.99	8.22	11.30	6.15
15	मध्य प्रदेश	49	17.15	15.97	19.36	0.11	0.10	0.00
16	महाराष्ट्र	47	36.87	36.76	34.29	22.88	37.60	1.28
17	मणिपुर	11	7.41	8.11	6.08	0.00	0.00	0.00
18	मेघालय	12	0.43	0.42	0.41	0.15	0.00	0.01
19	मिजोरम	3	0.32	0.30	0.36	0.01	0.00	0.00
20	नागालैंड	8	0.73	0.69	0.68	0.00	0.00	0.00
21	ओडिशा	40	10.31	9.94	9.80	1.25	3.80	3.76
22	पंजाब	47	3.56	3.38	3.45	1.71	2.60	1.58
23	राजस्थान	38	5.80	4.82	5.30	0.39	0.10	0.10
24	सिक्किम #	-	-	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	35	77.51	77.32	76.88	7.73	6.20	1.24
26	तेलंगाना	14	10.09	9.62	9.60	0.50	0.50	0.06
27	त्रिपुरा	5	2.76	2.80	2.88	0.38	0.20	0.01
28	उत्तराखंड	24	7.95	9.28	9.00	0.22	0.30	0.05
29	उत्तर प्रदेश	99	35.05	32.52	28.43	0.41	1.50	0.08
30	पश्चिम बंगाल	77	78.91	77.67	77.61	0.47	1.20	0.00
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	0.40	0.43	0.43	0.11	0.40	0.00
32	चंडीगढ़	2	0.24	0.19	0.19	0.08	0.20	0.08
33	दादर और नगर हवेली	1	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
34	दमन और दीव	2	0.11	0.11	0.10	0.00	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	1	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
36	पुडुचेरी	1	2.09	2.13	2.25	0.09	0.10	0.00
	योग@	**997**	**435.03**	**433.76**	**428.60**	**394.99**	**405.50**	**294.12**

स्रोत: रोजगार कार्यालय सांख्यिकी, रोजगार महानिदेशालय

टिप्पणी: # इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है;

@ हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।